



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या

- 4376 वर्ष 2026

सलमान @ डेविड

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कृपा शंकर मिश्रा, मृत्युंजय द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 113 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 304(2), 331(4), 317(2), थाना जावां, जनपद अलीगढ़ में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है तथा उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी आवेदक तथा सह-अभियुक्त बंटी के विरुद्ध चार दिन की विलम्ब से इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि आवेदक तथा सह-अभियुक्त ने सोने की हँसली की चोरी की। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त बंटी, जिसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था तथा जिसके कब्जे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से कथित रूप से ₹500 के 40 नोट बरामद हुए थे, को विचारण न्यायालय द्वारा ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे प्रस्तुत किया गया कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त मुकदमे में आवेदक को किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य [(2020) 5 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए ही नहीं दी जानी चाहिए। उपर्युक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक भी जारी रह सकती है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रदत्त अग्रिम जमानत, अभियुक्त के आचरण एवं व्यवहार पर निर्भर करते हुए, आरोप-पत्र दाखिल होने के पश्चात भी विचारण तक जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना, जिसमें साक्षियों को धमकाने की संभावना भी सम्मिलित है, तथा न्याय से पलायन अर्थात् देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना आवश्यक है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालयों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए, जब यह निर्णय लेना हो कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या अस्वीकार की जाए। यह प्रश्न कि जमानत दी जाए या नहीं, पूर्णतः न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है।

6. अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त सहवर्ती तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा गुण-अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में यह प्रकरण आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- **सलमान @ डेविड**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, इस आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर विचारण न्यायालय/विवेचक के समक्ष, जैसी भी स्थिति हो, उपस्थित होगा तथा विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह न्यायालय के समक्ष ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, साथ ही निम्न शर्तों के अधीन रहे:-

(i) आवेदक स्वयं को विवेचक/संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपलब्ध कराएगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा तथा यदि उसके पास पासपोर्ट है तो उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेगा।

9. यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वही आवेदक को प्रदान की गई संरक्षण/जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

2 जून, 2026

के. के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।